परेशान होम बायर्स की मदद के लिए मोदी सरकार ने बनाया मास्टर प्लान

नई दिल्ली, 10 फरवरी (ए)। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार होम बायर्स के रास्ते आम जनता के बीच पकड़ मजबूत करने का रास्ता तलाश रही है। इसके लिए चार बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पैसों की कमी से रुके पड़े आधा दर्जन बिल्डिंग प्रॉजेक्ट्स को फंड देने का ऑफर दिया है, जिससे उनका काम इसी साल फिर से शुरू हो सके। बैंकों ने इसके लिए नैशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (हडको) से भी बात की है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि सरकार ने हडको से ऐसे प्रॉजेक्ट्स की लिस्ट मांगी है, साथ ही यह भी पूछा है कि उन्हें पूरा करने के लिए कितनी रकम की जरूरत होगी। मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार चाहती है कि

यह प्लान जल्द से जल्द फाइनल हो जाए, जिससे 2019 आम चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले काम शुरू किया जा सके। ऐसा करके सरकार दिखाना चाहती है कि वह बिल्डर्स द्वारा सताए गए होम बायर्स के साथ है। पहले के खराब अनुभवों के चलते बैंकों ने सरकार से साफ कहा है कि वह फंड देने को तब ही राजी होंगे जब अपार्टमेंट्स और खाली पड़ी जमीन को उनके पास तबतक गिरवी रखा जाए। बैंकों का कहना है कि प्रॉजेक्ट्स के पूरा होने पर वह उन फ्लैट्स को बेचकर अपना पैसा निकालेगा। बैंक सिर्फ उन्हीं प्रॉजेक्ट्स को पैसा देने का मूड बना रहे हैं जिन्हें इस वक कहीं और से फंडिंग नहीं मिल रही। फंड देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक आदि आगे आए हैं। बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 3 लाख होम बायर्स अपना फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यहां अटका पड़ा काम केंद्र और यूपी सरकार दोनों के लिए बड़ा सिरदर्द है। अब आम्रपाली मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करनेवाला है, इसके बाद आगे की दिशा साफ हो सकती है।

रिक्शा चालकों और रेहड़ी वालों को 60 साल के बाद पाना है पेंशन, तो 15 फरवरी से कराना होगा रजिस्ट्रेशन

नयी दिल्ली, 10 फरवरी (ए)। यदि आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और रिटायरमेंट की उम्र के बाद पेंशन पाने की लालसा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मोदी सरकार का श्रम मंत्रालय कह रहा है. श्रम मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि असंगठित क्षेत्र के 40 साल तक की उम्र के कामगार दो दिन बाद यानी 15 फरवरी से ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) योजना से जुड़ सकते हैं. यह जानकारी श्रम मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके दी है.श्रम मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये हर महीने पेंशन दी जायेगी. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019-20 में इस योजना की घोषणा की है. योजना का उद्देश्य 15,000 रुपये तक की हर महीने कमाने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन उपलब्ध कराना है.गोयल ने कहा कि इस योजना से अगले पांच साल में 10 करोड़ कामगारों के योजना से जुड़ने की उम्मीद है. इसके लिए अंतरिम बजट में 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. उन्होंने बजट में कहा था कि योजना को चालू वित्त वर्ष से ही लागू कर दिया जायेगा. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन से लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये की हर महीने पेंशन दी जायेगी. इस योजना के तहत योजना से जुड़ने वाले कामगारों को बहुत ही छोटी राशि हर महीने पेंशन योजना में जमा करानी होगी।

देश में एम्स जैसे और संस्थान खोले जा रहे हैं : जेपी नड्डा

चंडीगढ़,10 फरवरी (ए)। केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में एम्स जैसे कई संस्थान खोल रहा है और मेडिकल कॉलेजों के नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नड्डा यहां स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) के 35 वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। नड्डा इस संस्थान के अध्यक्ष भी हैं। नड्डा ने केंद्र सरकार की पहलों का जिक्र करते हुए कहा, ''हम देश के विभिन्न हिस्सों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थान खोल रहे हैं। हम बड़े पैमाने पर जिला अस्पतालों का मेडिकल कॉलेजों के रूप में उन्नत कर अपने मेडिकल कॉलेजों के नेटवर्क का भी विस्तार कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाएं लाने से गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में पूर्ण बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) को 31 अक्टूबर,2018 को पीजीआईएमईआर में लागू किया गया और उसके तहत करीब 177 मरीजों का इलाज किया गया। दीक्षांत समारोह में पीजीआईएमईआर के 1886 विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में डिग्रियां प्रदान की गयी। केंद्रीय मंत्री ने उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए 35 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। इसके अलावा 92 को रजत पदक और 95 को कांस्य पदक प्रदान किये गये।

एसबीआई दे रही 5 लाख जीतने का मौका

नई दिल्ली, 10 फरवरी (ए)। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हैकथॉन - प्रीडिक्ट फॉर बैंक 2019 - की घोषणा की है, जिसके तहत बैंक 5,00,000 रुपये तक के नकद पुरस्कार दे रहा है। इसमें प्रतिभागी टीमों और व्यक्तियों को एक भविष्यवाणी कहनेवाला विश्लेषिकी मॉडल प्रस्तुत करना जरूरी है, जिसके माध्यम से एक कॉर्पोरेट ग्राहक की ओर से लोन पर चूक की संभावना का अनुमान लगाया जा सके। एसबीआई प्रिडिक्ट फॉर बैंक 2019 के लिए रजिस्ट्रेशन 24 जनवरी 2019 से शुरू हो चुके हैं और इसकी आखिरी तारीख 7 फरवरी 2019 है। मिली जानकारी के मुताबिक जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं वे खुद या चार व्यक्तियों के एक समूह के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद हैकथॉन फेज - प्रोटोटाइप डेवलपमेंट 12 फरवरी 2019 से 5 मार्च 2019 तक अस्थायी रूप से आयोजित किया जाएगा। हैकथॉन के पूरा होने पर एसबीआई की ओर से 5,00,000 और 4,00,000 रुपये के पुरस्कार के लिए दो प्रतिभागियों का चयन किया जा सकता है। एसबीआई के मुताबिक, प्रत्येक शॉर्टलिस्टेड टीम को हैकथॉन फेज में एसबीआई कॉर्पोरेट ग्राहक के 20 नामों को दिया जाएगा और टीम को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का उपयोग करके इन ग्राहकों के अगले 6 महीनों में डिफ़ॉल्ट होने की संभावना बताना होगा। एसबीआई 6 महीने बाद विजेताओं की घोषणा करेगा। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि बैंक की ओर से लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। साथ ही एसबीआई को कोई संतोषजनक मॉडल नहीं मिलने पर बैंक कोई भी पुरस्कार नहीं देगा।

आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च की ये निवेश स्कीम

नई दिल्ली,10 फरवरी (ए)। आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट की नई रेंज लॉन्च की है। बैंक ने इसका नाम एफडी एक्सट्रा दिया है। इनमें घर और रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की शिक्षा कार का डाउनपेमेंट आदि के लिए बचत शामिल हैं। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के इसकी नई रेंज कुछ दिनों के भीतर ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। बता दें कि बाजार में अस्थिरता के माहौल को देखते हुए ग्राहकों की फिक्स्ड और रेकरिंग डिपॉजिट में दिलचस्पी लौटी है। चुकी इनमें ब्याज दरें अच्छी हैं और इनके साथ पूंजी की सुरक्षा और एश्योर्ड रिटर्न जैसी बातें हैं इसलिए इसपर ग्राहक इसमें निवेश करना चाहते हैं। गौरतलब है कि एक फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीमों में निवेश करने वालों को राहत की घोषणा की है। इस तरह की एफडी पर 40,000 रुपये तक की ब्याज आय पर अब टीडीएस नहीं कटेगा। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के इस घोषणा के बाद लोग एफडी और आरडी में ज्यादा निवेश करने के लिए आगे आएंगे। मालूम हो कि एफडी एक्स्ट्रा डिपॉजिट का पहला वैरियंट एफडी लाइफ होगा। इसमें 18-50 उम्र के ग्राहकों को दोहरा बेनिफिट मिलेगा। इसमें एक तरफ एफडी के जरिए निवेश की राशि बढ़ेगी वहीं, फ्री टर्म इंश्योरेंस के साथ एफडी धारक को एक साल का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। कम से कम दो साल की अवधि के लिए 3 लाख रुपये की एफडी खोलने पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस से 3 लाख रुपये का टर्म लाइफ इंश्योरेंस मुफ्त मिलेगा। इसके दूसरे चरण में एफडी इंवेस्ट के जरिए ग्राहक फिक्स्ड डिपॉजिट से कमाए गए ब्याज को सिप के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे। ऐसे कर सकते हैं आवेदन-एफडी एक्स्ट्रा डिपॉजिट में आवेदन के लिए ग्राहक नजदीकी आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच जा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी एफडी इनकम के लिए आवेदन किया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक से जोखिम, आरक्षित भंडार के तौर पर रखे गए 27,380 करोड़ रुपये मांगे

नई दिल्ली,10 फरवरी (ए)। वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से 27,380 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की मांग की है। रिजर्व बैंक ने यह पूंजी पिछले कुछ वर्षों में जोखिम कवर और आरक्षित भंडार के तौर पर अपने पास रखी है। सूत्रों ने बताया है कि रिजर्व बैंक ने 2016-17 के दौरान जोखिम और आरक्षित भंडार के रूप में 13,190 करोड़ रुपये अपने पास रखे थे। वहीं 2017-18 में उसने 14,190 करोड़ रुपये रखे। इस तरह आरबीआई के पास कुल 27,380 करोड़ रुपये की राशि है। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष की साख पर चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बैंक से अंतरिम लाभांश देने और पिछले दो वित्त वर्षों के अधिशेष में से रखी गई राशि को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। इस महीने की शुरुआत में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा था कि चालू वित्त वर्ष में सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से 28,000 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश मिलने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार को रिजर्व बैंक से पहले ही 40,000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। यदि आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड अंतरिम लाभांश के रूप में सरकार के 28,000 करोड़ रुपये के अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो केंद्रीय बैंक द्वारा 2018-19 में कुल अधिशेष ट्रांसफर 68,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

वेदांत हॉस्पिटल व डाक्टर सेवा में कमी के दोषी, लगा जुर्माना

ग्वालियर, 10 फरवरी (ए)। वेदांत हॉस्पिटल कॉस्मैटिक सर्जरी एंड मेटिनिटी हॉस्पिटल ग्वालियर एवं डॉक्टर नमिता अग्रवाल (जनल सर्जन) को जिला उपभोक्ता फोरम ने संयुक्त रूप से सेवा में कमी का दोषी पाते हुए मैडीकल खर्च के साथ 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति व जुर्माना देने का आदेश दिया है। थाटीपुर इलाके में रहने वाली पुष्पा देवी नाम की महिला को जुलाई 2013 में पेट में दर्द की शिकायत हुई थी। उसने मुरार के वेदांत हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया जहां उसे पित्त की थैली में पथरी होने का हवाला देकर ऑपेशन करवाने की सलाह दी गई। महिला ने करीब 50,000 रुपए खर्च करने के बाद अपना ऑपेशन करवाया लेकिन उसके पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ, जबकि नर्सिंग होम का दावा था कि ऑपेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद महिला ने जयारोग्य चिकित्सालय में अपना इलाज करवाया। जहां उसका दोबारा ऑपेशन किया गया। जिससे उसे आराम मिल गया। इसके बाद महिला ने अक्तूबर 2014 में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम का दरवाजा खटखटाया।मामले की सुनवाई के दौरान फोरम ने महिला की शिकायत को सही पाते हुए वेदांत हॉस्पिटल और डॉक्टर नमिता अग्रवाल को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए आदेश दिया कि वह मरीज को उसके ऑपेशन पर हुआ सारा खर्चा लौटाने के साथ संयुक्त रूप से 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति पीड़िता को दे।

बैंक दे रहे एजेंसियों को ग्राहकों की डिटेल

नई दिल्ली, 10 फरवरी (ए)। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 जनहित याचिका (PIL) दाखिल हुई है। इस पर उसने केंद्र और रिजर्व बैंक से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि बैंकों द्वारा ग्राहकों के पैन (PAN) और वित्तीय लेन-देन के आंकड़ों को ग्राहकों की बिना सहमति अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाई जाए।मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक को नोटिस भेजकर इस पर उनका रुख बताने को कहा है। याचिका में दावा किया गया है कि ग्राहकों के स्थायी खाता संख्या (PAN) और अन्य लेन-देन को ट्रांसयूनियन सिबिल जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से साझा किया जा रहा है जो उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता अभिजीत मिश्रा ने कहा कि बैंक सिबिल जैसी एजेंसियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला करते हैं कि क्या संबंधित ग्राहक को कर्ज दिया जाए या क्रेडिट कार्ड जारी किया जाए। यहां तक कि इसी के आधार पर वे ब्याज दर भी तय करते हैं।अधिकता पायल बहल के माध्यम से जारी याचिका में मिश्रा ने कहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ग्राहक के पैन या अन्य वित्तीय लेनदेन को बैंकों द्वारा किसी निजी या गैर सरकारी इकाई को साझा करने के बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। याचिका में कहा गया है कि आयकर कानून, 1961 में भी नागरिकों के पैन आंकड़े को सिबिल जैसी एजेंसियों को साझा करने की अनुमति नहीं है।

आर्थिक आंकड़ों, वैश्विक संकेतों और तिमाही परिणाम से तय होगी शेयर बाजार की दिशा

मुंबई, 10 फरवरी (ए)। बीते सप्ताह तेजी में रहने वाले घरेलू शेयर बाजार का रुख अगले सप्ताह वैश्विक संकेतों, कच्चे तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव, आर्थिक आंकड़ों और दिग्गज कंपनियों के तिमाही परिणाम से तय होगा। बीते सप्ताह कारोबार के आखिरी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में रही भारी बिकवाली के बावजूद बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 77.05 अंक की साप्ताहिक बढ़त के साथ 36,546.48 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 49.95 अंक की तेजी के साथ 10,943.60 अंक पर पहुंच गया। हालांकि इस दौरान छोटी और मंझोली कंपनियों पर बिकवाली का दबाव हावी हो गया। बीएसई का मिडकैप 312.57 अंक यानी 2.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 14,328.813अंक पर और स्मॉलकैप 293.70 अंक यानी 2.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 13,656.75 अंक पर आ गया। आगामी सप्ताह 12 फरवरी को खुदरा महंगाई दर और औद्योगिक उत्पादन तथा 14 फरवरी को थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी होने हैं। इसके अलावा 10 फरवरी को आंध्रा बैंक, आइशर मोटर्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, स्पाइस जेट, 12 फरवरी को कोल इंडिया, बाटा इंडिया, हिंडाल्को, सन फार्मा, करुर वैश्य बैंक, 13 फरवरी को अडानी गैस , रिलायंस कैपिटल तथा 14 फरवरी को ग्लेनमार्क फार्मा, नेस्ले इंडिया, ओएनजीसी और वोल्टास के तिमाही परिणाम होने हैं। निवेशकों की नजर इन कंपनियों के तिमाही परिणाम पर रहेगी। इसके अलावा गत सप्ताह जारी टाटा स्टील के परिणाम का असर भी शेयर बाजार पर दिखेगा। वैश्विक स्तर पर अमेरिका-चीन विवाद,चीन की मुद्रास्फीति दर के आंकड़े, अमेरिका की खुदरा बिक्री के आंकड़े और जापान के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े निवेश धारणा को प्रभावित करेंगे। बीते सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह एक मार्च की डेडलाइन से पहले चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से नहीं मिल पाएंगे, जिसके बाद शेयर बाजार में भूचाल आ गया।
आगले सप्ताह भी इस बयान का असर शेयर बाजार पर रहेगा।

ए.टी.एम.से कैश निकालना हो सकता है महंगा,एनपीसीआई ने रखा इंटरचेंज चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, 10 फरवरी (ए)। आने वाले समय में ए.टी.एम. से कैश निकालना महंगा पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि नैशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने कैश विदड्रॉल्स के लिए इंटरचेंज चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इंटरचेंज चार्ज वह अमाउंट होती है जो ए.टी.एम. ऑपरेटर्स से प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए वसूला जाता है। एन.पी.सी.आई. ने इंटरचेंज फीस बढ़ाने की सिफारिश ऐसे समय की है जब ए.टी.एम. का संचालन करने वाली कम्पनियां पहले ही लागत बढ़ने की बात कह रही हैं। ऐसे में अगर सरकार इंटरचेंज फीस बढ़ाती है तो ए.टी.एम. संचालन करने वाली कम्पनियों की लागत और बढ़ेगी। ऐसे में इसका बोझ ए.टी.एम. से पैसे निकालने वालों को भी उठाना

पड़ सकता है। ए.टी.एम. सर्विस प्रोवाइडर करवाने वाली कम्पनी के एक अधिकारी का कहना है कि इंटरचेंज फीस पिछले 6 साल से उसी स्तर पर है। यह ए.टी.एम. से प्रति ट्रांजैक्शन पर आने वाली लागत से भी कम है। ऐसे में इंटरचेंज फीस बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं इंटरचेंज फीस का भुगतान करने वाले बैंक इसमें इजाफा नहीं चाहते हैं। अधिकारी का कहना है कि अगर इंटरचेंज फीस नहीं बढ़ाई जाती है तो इसमें नियामक को हस्तक्षेप करना चाहिए। इंटरचेंज फीस एन.पी.सी.आई. की स्टीयरिंग कमेटी तय करती है। इसमें प्रमुख रूप से बैंक के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। एन.पी.सी.आई. ने सिफारिश की है कि इंटरचेंज फीस को 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया जाना चाहिए। हालांकि एन.पी.सी.आई. की स्टीयरिंग कमेटी में इंटरचेंज फीस को लेकर आम राय नहीं है। स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों ने एन.पी.सी.आई. से अनुरोध किया है कि इस मामले में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशियल सर्विसेज की सलाह ली जानी चाहिए। मौजूदा समय में बैंक अपने डेबिट कार्ड होल्डर को एक माह में ए.टी.एम. से 3 से 4 कैश विदड्रॉल की सुविधा फ्री में देते हैं। इससे अधिक ट्रांजैक्शन होने पर बैंक प्रति ट्रांजैक्शन 10 से 15 रुपए तक चार्ज करते हैं। अगर इंटरचेंज चार्ज बढ़कर 15 से 17 रुपए हो जाती है तो बैंकों को प्रति ट्रांजैक्शन ए.टी.एम. सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों को ज्यादा पैसा देना होगा। ऐसे में बैंक ए.टी.एम. से कैश विदड्रॉल पर चार्ज बढ़ा सकते हैं।

आईडीएफसी का शुद्ध मुनाफा दिसंबर तिमाही में 11 गुणा बढ़कर 26 करोड़ रुपए हुआ

नई दिल्ली, 10 फरवरी (ए)। आईडीएफसी का शुद्ध मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर में समाप्त तिमाही में 11 गुणा बढ़कर 26.28 करोड़ रुपए हो गया। कर समायोजन से कंपनी के मुनाफे में यह वृद्धि हासिल की गई है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में उसका एकल शुद्ध मुनाफा 2.40 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी ने कहा कि आलोच्य तिमाही के दौरान उसकी कुल आय 13.26 करोड़ रुपए से कम होकर 7.87 करोड़ रुपए रह गई। कंपनी ने कहा कि आलोच्य तिमाही के दौरान उसके तिमाही परिणाम पर रहेगी। इसके अलावा गत सप्ताह जारी टाटा स्टील के परिणाम का असर भी शेयर बाजार पर दिखेगा। वैश्विक स्तर पर अमेरिका-चीन विवाद,चीन की मुद्रास्फीति दर के आंकड़े, अमेरिका की खुदरा बिक्री के आंकड़े और जापान के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े निवेश धारणा को प्रभावित करेंगे। बीते सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह एक मार्च की डेडलाइन से पहले चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से नहीं मिल पाएंगे, जिसके बाद शेयर बाजार में भूचाल आ गया।
आगले सप्ताह भी इस बयान का असर शेयर बाजार पर रहेगा।

दवाओं के कीमत दाम तय करने का बनेगा नया फार्मूला!

नई दिल्ली, 10 फरवरी (ए)। मूल्य नियंत्रण के दायरे में आने वाली दवाओं के दाम तय करने के लिए नया फार्मूला बनाए जाने के संकेत हैं। माना जा रहा है कि मौजूदा फार्मूले से दवाओं के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने का मकसद भी नाकाम हो रहा है यानी कि लोगों को अब दवा की कीमतें भी दर्द देने लगी हैं।गौरतलब है कि वर्ष 2013 से पहले दवा की लागत के हिसाब से उसका दाम तय किया जाता था। सूत्रों का कहना है कि सरकार एक बार फिर दवा की

लागत के हिसाब से उसके दाम तय करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो मूल्य नियंत्रण के दायरे में आने वाली दवाओं के दाम कम हो सकते हैं। दरअसल मौजूदा सिस्टम में दवाओं के दाम तय करने के लिए बनाए गए फार्मूले का इसे बनाए जाने के समय से ही विरोध हो रहा है। कई नागरिक संगठन और एन.जी.ओ. सरकार से लगातार इसे बदलने की मांग कर रहे हैं। दवाओं के दाम तय करने का मौजूदा सिस्टम 2013 के ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के जरिए वजूद में आया था। इसका मकसद आम जनता को वाजिब दाम पर जरूरी दवाएं मुहैया करवाना था।इस फार्मूले के मुताबिक मूल्य नियंत्रण के दायरे में आने वाली किसी भी कम्पनी की दवा की बाजार में एक प्रतिशत हिस्सेदारी जरूरी है। ऐसी दवा को बनाने वाली हर कम्पनी की दवा के दामों का औसत निकाला जाता है और फिर उसके हिसाब से कीमत तय की जाती है। हर साल इसमें 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी की जा सकती है। इससे दवाओं के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। दवा की कीमतों पर नियंत्रण नहीं होने और विक्रेताओं की इस मनमानी को लेकर निजामाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने शिकायती पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू तक भेजा है। उसका दावा है कि खुदरा विक्रेता 30 गुना तक मुनाफा वसूल रहे हैं। संगठन ने इस पर नीति बनाने की मांग की है ताकि आम नागरिकों से होने वाली लूट को रोका जा सके। पत्र के साथ चैंबर ने 1097 दवाओं की सूची पी.एम.ओ. को भेजी है जिन्हें 100 से लेकर 2100 प्रतिशत से अधिक दामों पर बेचा जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि देशभर में दवाओं की अधिकतम कीमत तय कर दी जाए तो चिकित्सा खर्च में 85 से 90 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।